पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः ज्येष्ठ 16, 1944
सोमवारः 06 जून 2022

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देते हुए 76,महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने वाले 76,390 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भरता' के आह्वान के आलोक में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 06 जून 2022 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए '(भारतीय) खरीदें', '(भारतीय) खरीदें व बनाएं और खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम) ' श्रेणियों के तहत 76,390 करोड़ रुपये मूल्य की आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और विदेशी खर्च में काफी कमी आएगी।

भारतीय सेना के लिए, डीएसी ने स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर देते हुए घरेलू स्रोतों के माध्यम से रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स (आरटीएफएलटी), ब्रिज बिछाने वाले टैंक (बीएलटी), पहिएदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहन (डब्ल्यूएच एएफवी) के साथ एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (एटीजीएम) और वेपन डिटेक्टिंग रडार (डब्ल्यूएलआर) की खरीद के लिए नई आवश्यकता (एओएन) की स्वीकृति प्रदान की।

भारतीय नौसेना के लिए, डीएसी ने लगभग 36,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कार्वेट (एनजीसी) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। ये एनजीसी विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं जैसे निगरानी मिशन, अनुरक्षण संचालन, शक्ति संतुलन, सरफेस एक्शन ग्रुप (एसएजी) ऑपरेशन्स, खोज एवं हमले और तटीय रक्षा के लिए बहुमुखी मंच होंगे। इन एनजीसी का निर्माण पोत निर्माण की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके भारतीय नौसेना के नए इन-हाउस डिजाइन के आधार पर किया जाएगा और यह सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।

डीएसी ने नवरत्न सीपीएसई मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स और एसयू-30 एमकेआई एयरो-इंजनों के विनिर्माण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें विशेष रूप से एयरो इंजन सामग्री के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप (भारतीय) खरीदें' श्रेणी के अंतर्गत डिजिटल तटरक्षक परियोजना को डीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के तहत तटरक्षक बल में विभिन्न सतही और विमानन परिचालन, रसद, वित्त और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए एक अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

एबीबी/डीके/डीएस/आरपी